समुद्र की लहरों से विद्युत उत्पादन

2816. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री राम नरेश यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा देश में समुद्र की लहरों से विद्युत उत्पादन करने के लिए एक योजना कार्यान्वित की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की अनुमानित लागत कितनी है और इस योजना के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन की लागत कितनी आने की सभावना है; और

(ग) इस योजना को कब तक पूरा किये जाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) यह योजना त्रिवेन्द्रम के निकट विझिजम में लगभग 106 लाख रु० की लागत से प्रायोगिक आधार पर आरम्भ की जा रही है । तरंग विद्युत संयत्र द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत लगभग 2.20 रु० प्रति किलोवाट/घंटा होगी ।

(ग) इसे 1989 के मध्य तक पूरा किए जाने की आशा है ।

पाकिस्तान की परमाणु योजनाएं

2817. **श्री पवन कुमार बांसल**
श्री मुरलीधर चन्द्रकान्त भंडारे :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने इस वर्ष भूमि से भूमि तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र "किंग हाक" का परीक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इससे इस क्षेत्र के सुरक्षा के माहौल पर क्या असर पड़ा है ; और

(ग) पाकिस्तान की परमाणु योजनाओं द्वारा पेश की गई नई चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत की वर्तमान क्षमता क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) सरकार ने इस संबंध में मीडिया रिपोर्ट देखी है लेकिन उसके पास इस बारे में कोई पक्की सूचना नहीं है। सरकार देश की सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली सभी गतिविधियो की सतत समीक्षा करती है और पर्याप्त रक्षा तैयारी के लिए उपयुक्त उपाय करती है ।

Defence Factories in M.P.

2818. THAKUR JAGATPAL SINGH : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Defence factories in Madhya Pradesh have not been taking any interest in establishing ancillary industries for the last sixteen years despite the instructions issued by the Ministry in this regard in July, 1971;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) what is the quantum of work allocated to the existing ancillary industries?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI) : (a) It is not a fact that adequate interest is not taken by Ordnance Factories in Madhya Pradesh for promoting ancillary units despite the issue of instructions issued by the Ministry in this regard in July, 1971.

(b) The slow progress in the development of ancillary units is because the nature of items which could be procured from civil trade for use in manufacture of armament and ammunition and their components do not easily lend themselves to production in ancillary units wherein by definition investment in plant and machinery is not to exceed Rs. 45 lakhs and which must yet meet the stringent requirements of quality specifications and timely delivery conditions. Therefore the scope for developing ancillary units is limited.

(c) The value of work paid for to ancillary industries in the last four years was :—

Year	(Rs. in crores) Value
1984-85	3.00
1985-86	2.60
1986-87	3.30
1987-88	3.03

Removal of shipwrecks from the sea

2819. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK :

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appeared in the 'Hindustan Times' dated the 27th June 1988 wherein it has been stated that India's Coastline abounds with more than 200 shipwrecks dating back to 400 years;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether any steps are being taken by Government for the removal of such wrecks of ships from the sea; and

(d) if not, what are the reason therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE (SHRI K.R. NARAYANAN) : (a) Yes, Sir.

(b) 210 shipwreck sites in and around the country have been identified, distributed in 17 shipwreck zones. The identification has been based on the marine records of State Archieves of Bombay, Madras and Calcutta. Preliminary survey in Goa and Tranquebar of Tamilnadu coasts reveals one shipwreck each.

(c) and (d) No Sir. The work of project involves collection of data and location sites.